National Research Journal of Social Sciences
A Bi-annual Refereed Journal
PP: 126-133
Volume-9, Issue-2, July 2024 to December 2024
ISSN: 2348-473X
Impact Factor: 4.90

मधुबनी और दरभंगा में घरेलू कामकाज में दलित बच्चों की भागीदारी के संदर्भ में अदृश्य श्रम और नागरिक समाज की भूमिका

संजय कुमार झा

पूर्व शोधार्थी

समाजशास्त्र विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्विद्यालय, दरभंगा

सारांश

मधुबनी और दरभंगा में बच्चों का श्रम केवल उन कार्यों तक सीमित नहीं है जो बाजार या कार्यस्थल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। घर के भीतर होने वाले कामकाज, जैसे देखभाल-कार्य, पानी और ईंधन लाना, घर-आँगन की सफाई, पशु-देखभाल, छोटे भाई-बहनों की निगरानी, तथा घरेलू उद्यम में सहायता, बड़ी मात्रा में बच्चों द्वारा किए जाते हैं। यह श्रम प्रायः पारिश्रमिक-रहित होता है और "घर का काम" मानकर न तो परिवार इसे श्रम की श्रेणी में रखता है, न ही यह नियमित आँकड़ों, नीति-निगरानी और सार्वजनिक विमर्श में पर्याप्त रूप से दर्ज हो पाता है। इसी कारण यह श्रम 'अदृश्य' बन जाता है, जबकि इसका समय-भार और जिम्मेदारी बच्चों की शिक्षा, विश्राम, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर वास्तविक प्रभाव डाल सकती है। दलित परिवारों में यह स्थिति और जटिल हो जाती है क्योंकि गरीबी, अस्थिर आजीविका, मौसमी प्रवासन, सामाजिक बहिष्करण तथा जाति-आधारित श्रम-विभाजन मिलकर बच्चों पर घरेलू दायित्वों का दबाव बढ़ा देते हैं। यह शोध-पत्र अदृश्य श्रम की अवधारणा के माध्यम से मधुबनी-दरभंगा में दलित बच्चों के घरेलू श्रम को समझने का प्रयास करता है, जोखिम के सामाजिक भूगोल को संकेतक-आधारित दृष्टि से रखता है, और नागरिक समाज की भूमिका को स्पष्ट करता है, विशेषकर पहचान, जागरूकता, शिकायत-समर्थन, संस्थागत समन्वय और पुनर्वास-अनुवर्तन के संदर्भ में। निष्कर्षतः, घरेलू श्रम की अदृश्यता को तोड़े बिना बाल-अधिकार और शिक्षा-निरंतरता के लक्ष्य टिकाऊ रूप से प्राप्त नहीं किए जा सकते।

कूट शब्द: अदृश्य श्रम, घरेलू कामकाज, दलित बच्चे, मधुबनी, दरभंगा, नागरिक समाज, बाल-अधिकार, शिक्षा-निरंतरता, सामाजिक बहिष्करण

1. परिचय

बाल श्रम पर सार्वजनिक बहस और नीति-चर्चा का झुकाव प्रायः उन्हीं क्षेत्रों की ओर रहता है जहाँ श्रम प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, जैसे दुकान, ढाबा, निर्माण-स्थल या ईंट-भट्ठा। इस दृश्यता के कारण नीति-निगरानी, बचाव-कार्रवाई और आँकड़ा-रिपोर्टिंग भी अधिकतर ऐसे ही कार्यस्थलों पर केंद्रित हो जाती है।

© Copyright @ Authors

Volume-9, Issue-2, July 2024 to December 2024
ISSN: 2348-473X
Impact Factor: 4.90

पर बच्चों का श्रम अनुभव इससे कहीं व्यापक है, क्योंकि घर के भीतर होने वाला कामकाज अक्सर "श्रम" की तरह नहीं पहचाना जाता। घरेलू कामकाज में बच्चों की भागीदारी को परिवार-दायित्व, सहायता या संस्कार के रूप में परिभाषित कर दिया जाता है, जिससे यह काम 'श्रम' के सामाजिक अर्थ से बाहर हो जाता है। यही अर्थ-निर्माण घरेलू श्रम को अदृश्य बना देता है और इसे नीति-विमर्श से भी बाहर धकेल देता है।

अदृश्यता का यह अर्थ यह नहीं कि घरेलू कामकाज का प्रभाव नगण्य है। जब बच्चों पर घरेलू कामकाज का समय-भार बढ़ जाता है, तब यह उनके समय-अधिकार को सीमित करता है और शिक्षा के साथ टकराव पैदा करता है। कई स्थितियों में बच्चा स्कूल जाता भी है, पर थकान, देर से पहुँचना, गृहकार्य न कर पाना, पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय न मिलना और नियमित अनुपस्थिति जैसे संकेत धीरे-धीरे उसकी सीखने की निरंतरता को कमजोर करते हैं। यही क्रम आगे चलकर स्कूल-छोड़ने के जोखिम को बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू कामकाज अगर बच्चों की सुरक्षा और गरिमा को प्रभावित करे, जैसे अत्यधिक जिम्मेदारी, एकाकीकरण, अनुशासन के नाम पर कठोर व्यवहार, या काम के कारण चोट/स्वास्थ्य-हानि, तो यह बाल-अधिकार के दृष्टिकोण से गंभीर हस्तक्षेप-क्षेत्र बन जाता है।

इसी बिंदु पर परिभाषात्मक स्पष्टता आवश्यक हो जाती है। घरेलू कामकाज हर स्थिति में बाल श्रम नहीं होता, क्योंकि परिवार में बच्चों का सीमित स्तर का योगदान कुछ संदर्भों में सामाजिक जीवन का हिस्सा हो सकता है। पर जब घरेलू काम आयु-मानकों से टकराए, काम की प्रकृति हानिकारक हो, या समय-भार इतना बढ़ जाए कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने लगे, तब यह जोखिम-श्रेणी में प्रवेश कर जाता है। यह सीमा-रेखा अंतरराष्ट्रीय मानकों और सूचकांकों में स्पष्ट की गई है, जहाँ उम्र, काम की प्रकृति तथा समय-भार को निर्णायक कसौटी माना जाता है। [1], [2] इस प्रकार घरेलू श्रम को समझने का उद्देश्य किसी परिवार-विशेष को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि यह पहचानना है कि कब घरेलू जिम्मेदारी बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं और अधिकारों का ह्रास करने लगती है।

मधुबनी और दरभंगा के संदर्भ में यह प्रश्न इसलिए और अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर बिहार में अस्थिर आजीविका, मौसमी बेरोजगारी और प्रवासन जैसी स्थितियाँ घरेलू श्रम-वितरण की संरचना को प्रभावित करती हैं। जब वयस्क सदस्य बाहर काम के लिए जाते हैं, या आय-स्रोत अस्थिर होता है, तब घर के भीतर कार्यों का पुनर्वितरण होता है और बच्चों पर जिम्मेदारी बढ़ सकती है। दलित परिवारों में सामाजिक बहिष्करण और संसाधन-घाटा इस दबाव को और तीखा कर देता है, क्योंकि सेवाओं तक पहुँच की बाधाएँ और कम सामाजिक पूँजी कई बार बच्चों को जल्दी "घरेलू जिम्मेदारी" के चक्र में बाँध देती हैं। इसलिए मधुबनी और दरभंगा का अध्ययन केवल घरेलू दायरे का अध्ययन नहीं रह जाता; यह सामाजिक-आर्थिक संरचना, जाति-आधारित असमानता और बच्चों के अधिकारों के बीच संबंध को समझने का समाजशास्त्रीय प्रयास बन जाता है। जिला-स्तरीय बाल-श्रम संकेतों में इन दोनों जिलों की उपस्थिति भी यही

© Copyright @ Authors

Volume-9, Issue-2, July 2024 to December 2024
ISSN: 2348-473X
Impact Factor: 4.90

बताती है कि समस्या केवल सूक्ष्म घरेलू दायरे तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापक संरचनात्मक वास्तविकताओं से जुड़ी है। [3]

2. अध्ययन क्षेत्र

मधुबनी और दरभंगा मिथिला क्षेत्र के प्रमुख जिले हैं, जहाँ ग्रामीण आबादी का अनुपात बड़ा रहा है और रोजगार-संरचना में कृषि, असंगठित श्रम तथा प्रवासन-आधारित आय की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। ऐसी संरचना में घर-के-भीतर श्रम की "आवश्यकता" बढ़ जाती है, क्योंकि वयस्क सदस्यों का समय बाहर के काम और अस्थिर आय-प्रबंधन में जाता है। बच्चों द्वारा घरेलू कामकाज का अर्थ केवल "घर चलाना" नहीं, बल्कि परिवार की श्रम-क्षमता का विस्तार है। दलित बस्तियों में यह विस्तार अक्सर सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच की बाधाओं, कम सामाजिक पूँजी और सामाजिक दूरी के साथ जुड़कर अधिक कठोर हो जाता है।

3. वैचारिक ढाँचा, शोध पद्धति और स्रोत

अदृश्य श्रम का तर्क यह है कि घरेलू श्रम, विशेषकर देखभाल-कार्य, समाज के पुनरुत्पादन का आधार है, पर इसकी गणना और मान्यता कमजोर रहती है। जब बच्चे घरेलू श्रम करते हैं, तो यह परिवार को तात्कालिक सुविधा देता है, पर बच्चे के समय-अधिकार, शिक्षा-निरंतरता, विश्राम और सुरक्षा को सीमित कर सकता है। इस "समय-चोरी" का प्रभाव अक्सर धीरे-धीरे दिखता है, जैसे देर से स्कूल पहुँचना, होमवर्क न होना, थकान, सीखने में पिछड़ना और अंततः स्कूल-छोड़ने का जोखिम।

इस प्रक्रिया में जाति-आधारित श्रम-विभाजन निर्णायक है। दलित परिवारों में घरेलू श्रम कई बार केवल घरेलू नहीं रह जाता, बल्कि पानी-ईंधन, सफाई-संबंधी काम, घरेलू पशु-देखभाल और अस्थायी छोटे कामों के साथ मिलकर "अर्ध-बाजार श्रम" बन जाता है। यह श्रम चूँकि घर-के-भीतर और बस्ती-स्तर पर फैलता है, इसलिए निगरानी से बाहर और सामान्यीकृत हो जाता है।

यह शोध-पत्र द्वितीयक साक्ष्य-आधारित समाजशास्त्रीय विश्लेषण है। जिला-स्तरीय संकेतों के लिए राज्य-स्तरीय दस्तावेज़ की जिला-वार सारणी का उपयोग किया गया है। [3] घरेलू कामकाज के समय-भार और स्कूल-काम सहअस्तित्व को समझने के लिए बिहार पर आधारित गुणात्मक निष्कर्षों का सहारा लिया गया है। [4] घरेलू कामकाज को जोखिम-श्रेणी में पहचानने के लिए मानक परिभाषाएँ और सूचक-सीमाएँ (घरेलू कार्य-सेवा की समय-सीमा सहित) अपनाई गई हैं। [1], [2] नागरिक समाज और संस्थागत समन्वय की चर्चा में राज्य-स्तरीय बाल-अधिकार कार्य-ढाँचे तथा संबंधित संस्थागत व्यवस्थाओं के उल्लेख उपयोग किए गए हैं। [3], [5]

© Copyright @ Authors

Volume-9, Issue-2, July 2024 to December 2024
ISSN: 2348-473X
Impact Factor: 4.90

4. परिणाम: जिला-स्तरीय संकेत और घरेलू श्रम-जोखिम का मापन-आधार

राज्य-स्तरीय दस्तावेज़ में 5–14 आयु-वर्ग के बाल-श्रमियों की जिला-वार संख्या उपलब्ध है। इस आधार पर मधुबनी और दरभंगा के लिए चयनित संकेत निम्न सारणी में दिए गए हैं। [3]

सारणी 1: 5–14 आयु-वर्ग के बाल-श्रमियों की संख्या (जिला-वार चयन)

इकाई	5–14 आयु-वर्ग के बाल-श्रमियों की संख्या	राज्य कुल में हिस्सा (प्रतिशत)
बिहार	1288321	10.99
मधुबनी	61523	4.78
दरभंगा	36256	2.81

(स्रोत: राज्य-स्तरीय बाल-अधिकार कार्ययोजना दस्तावेज़ में दी गई जिला-वार सारणी) [3]

यह सारणी “कुल कार्यरत बच्चों” का संकेत देती है, पर घरेलू श्रम की अदृश्यता के कारण यह मान लेना उचित नहीं कि घरेलू कामकाज यहाँ पूरी तरह दर्ज है। घरेलू श्रम कई बार रिपोर्टिंग में कम पकड़ में आता है, इसलिए इसे जोखिम-चित्र का न्यूनतम संकेत मानना अधिक उपयुक्त है।

घरेलू कामकाज को जोखिम-श्रम के रूप में पहचानने के लिए समय-सीमा महत्वपूर्ण है। मानक सूचक-ढाँचों में 5–14 आयु-वर्ग के लिए सप्ताह में 21 घंटे या उससे अधिक घरेलू कार्य-सेवा को गंभीर श्रम-भार का संकेत माना जाता है, क्योंकि इतना समय-भार स्कूलिंग और बच्चे के कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। [2]

सारणी 2: घरेलू कार्य-सेवा के लिए समय-सीमा आधारित जोखिम संकेत

आयु-समूह	घरेलू कार्य-सेवा (सप्ताह में)	जोखिम-सीमा
5–11	21 घंटे या अधिक	गंभीर श्रम-भार संकेत
12–14	21 घंटे या अधिक	गंभीर श्रम-भार संकेत

(स्रोत: बाल श्रम सूचक-ढाँचे में घरेलू कार्य-सेवा की समय-सीमा संबंधी मानक) [2]

© Copyright @ Authors

बिहार पर आधारित गुणात्मक निष्कर्ष यह संकेत देते हैं कि बच्चे स्कूल के साथ घरेलू कामकाज भी करते हैं और घरेलू काम का समय-भार वास्तविक है, जिससे स्कूल-काम सहअस्तित्व की चुनौती सामने आती है। [4] यह संकेत मधुबनी-दरभंगा के संदर्भ में इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि दलित परिवारों में घरेलू श्रम-भार अक्सर लिंग-आधारित असमानता के साथ जुड़ता है, जिससे लड़कियों पर समय-दबाव अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है। [4]

5. चर्चा: दलित बच्चों का घरेलू श्रम कैसे अदृश्य बनता है

घरेलू श्रम के अदृश्य बनने की पहली प्रक्रिया "नामकरण" की है। जब घरेलू काम को मदद, जिम्मेदारी या संस्कार कहा जाता है, तो वह श्रम-श्रेणी से बाहर हो जाता है। दूसरी प्रक्रिया "स्थान" की है, घर-के-भीतर होने वाला कार्य सार्वजनिक निरीक्षण से बाहर रहता है। तीसरी प्रक्रिया "अधिकार-भाषा" की है स्कूल और स्थानीय प्रशासन अक्सर अनुपस्थिति को समस्या मानते हैं, पर घरेलू श्रम-समय को व्यवस्थित कारण के रूप में दर्ज नहीं करते। चौथी प्रक्रिया "जाति-वर्ग-लिंग" के संयोजन की है, दलित बस्तियों में सेवा-घाटा, संसाधन-कमी और सामाजिक दूरी घरेलू श्रम-आवश्यकता बढ़ाती है, और उसी के साथ बच्चों का श्रम-समय सामान्यीकृत होता जाता है।

जब घरेलू श्रम स्कूलिंग से टकराता है, तो बच्चे का स्कूल-अनुभव कमजोर होता है और धीरे-धीरे बाहर होने का जोखिम बढ़ता है। अंतरराष्ट्रीय साक्ष्य बाल श्रम और स्कूलिंग को परस्पर-निर्भर प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, जहाँ स्कूल-रणनीतियाँ और शिक्षा-तंत्र की गुणवत्ता बाल श्रम घटाने में निर्णायक हो सकती है। [6], [7]

6. नागरिक समाज की भूमिका

घरेलू श्रम की अदृश्यता को तोड़ने में नागरिक समाज की भूमिका इसलिए केंद्रीय है क्योंकि वह समुदाय-स्तर पर भरोसा-आधारित काम कर सकता है। पहली भूमिका "पहचान और भाषांतरण" की है, अर्थात यह स्पष्ट करना कि अत्यधिक घरेलू श्रम-समय भी अधिकार-ह्रास हो सकता है और इसकी शिकायत/समर्थन का मार्ग क्या है। दूसरी भूमिका "शिकायत-समर्थन" की है जहाँ परिवार, स्कूल और स्थानीय संस्थाओं के बीच संवाद-सेतु की जरूरत होती है। तीसरी भूमिका "समन्वय" की है विशेषकर उन मामलों में जहाँ बच्चा घरेलू सेवक के रूप में तैनात हो, या घर-के-भीतर शोषण/हिंसा जैसी स्थितियाँ हों; ऐसे मामलों में बहु-एजेंसी कार्रवाई आवश्यक होती है। राज्य-स्तरीय बाल-अधिकार ढाँचे में बहु-स्तरीय व्यवस्थाओं और सहायता-तंत्रों का उल्लेख नागरिक समाज-राज्य समन्वय की जरूरत को पुष्ट करता है। [3], [5]

सबसे निर्णायक चरण "बचाव/हस्तक्षेप के बाद" आता है। यदि बच्चा स्कूल में लौट भी जाए, पर घरेलू श्रम-भार वही बना रहे, परिवार की आजीविका-दबाव कम न हो, और स्कूल-उपस्थिति का 6–24 महीनों तक अनुवर्तन न हो, तो बच्चे के फिर उसी श्रम-चक्र में लौटने की संभावना बनी रहती है। इसलिए नागरिक समाज की भूमिका को केवल जागरूकता-कार्य तक सीमित न रखकर अनुवर्तन-आधारित सहयोग-मॉडल में संस्थागत करना आवश्यक है। [7], [8]

© Copyright @ Authors

Volume-9, Issue-2, July 2024 to December 2024
ISSN: 2348-473X
Impact Factor: 4.90

7. नीतिगत निहितार्थ

पहला निहितार्थ यह है कि स्कूल-स्तर पर "समय-उपयोग" को नियमित निगरानी का हिस्सा बनाया जाए। 21 घंटे/सप्ताह जैसी सीमा-रेखा के आधार पर स्कूल-समर्थन, परिवार-परामर्श और समुदाय-आधारित सहायता को सक्रिय किया जा सकता है। [2]

दूसरा निहितार्थ यह है कि मधुबनी और दरभंगा में दलित बस्तियों के लिए स्कूल-समर्थन केवल पोशाक/भोजन तक सीमित न रहे, बल्कि सीखने-समर्थन, उपस्थिति-अनुवर्तन और घरेलू श्रम-भार घटाने के लिए परिवार-स्तरीय सहायता को जोड़ा जाए।

तीसरा निहितार्थ यह है कि जिला-स्तरीय बाल-श्रम संकेत (सारणी 1) को घरेलू श्रम-जोखिम मानचित्र के साथ जोड़ा जाए। मधुबनी का राज्य-कुल में हिस्सा अधिक है और दरभंगा की संख्या भी उल्लेखनीय है; इसलिए दोनों जिलों में लक्षित हस्तक्षेप की जरूरत बनती है। [3]

चौथा निहितार्थ यह है कि नागरिक समाज को औपचारिक साझेदार के रूप में शिकायत-समर्थन, विद्यालय-पुनर्स्थापन और अनुवर्तन-ढाँचे में स्थान दिया जाए, ताकि अदृश्य श्रम के मामलों की पहचान और सतत निगरानी संभव हो। [3], [5]

8. निष्कर्ष

मधुबनी और दरभंगा में दलित बच्चों का घरेलू कामकाज एक ऐसी व्यापक सामाजिक परिघटना है जो प्रायः "सामान्य" और "स्वाभाविक" मानकर अदृश्य कर दी जाती है, पर इसके परिणाम बच्चों के समय-अधिकार, शिक्षा-अवसर और नागरिक अधिकार-हकदारी पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ते हैं। घरेलू श्रम का एक बड़ा हिस्सा पारिश्रमिक-रहित होता है और परिवार इसे घर चलाने की अनिवार्य जरूरत या बच्चों की मदद के रूप में परिभाषित करता है। यही नामकरण घरेलू काम को श्रम के रूप में दर्ज होने से रोकता है। परिणामस्वरूप, नीति-निगरानी और सार्वजनिक विमर्श में घरेलू श्रम का वास्तविक समय-भार, काम की प्रकृति और उससे उत्पन्न जोखिम पर्याप्त रूप से पकड़ में नहीं आते। फिर भी यह श्रम बच्चों के दैनिक जीवन में लगातार उपस्थित रहता है और धीरे-धीरे स्कूल-उपस्थिति, सीखने की निरंतरता, स्वास्थ्य और मनोसामाजिक विकास पर दबाव बनाता है। जब बच्चा रोज़ाना कुछ घंटे घरेलू जिम्मेदारियों में लगाता है, तब स्कूल जाना तो संभव हो सकता है, लेकिन सीखने के लिए आवश्यक एकाग्रता, गृहकार्य, विश्राम और सुरक्षा का अनुभव कमजोर हो जाता है; और यही स्थिति आगे चलकर अनुपस्थिति, पिछड़ापन और अंततः स्कूल-छोड़ने के जोखिम को बढ़ा सकती है।

© Copyright @ Authors

जिला-स्तरीय संकेत इस समस्या के सामाजिक भूगोल को समझने में मदद करते हैं। उपलब्ध जिला-वार आँकड़े यह संकेत देते हैं कि मधुबनी और दरभंगा दोनों में 5–14 आयु-वर्ग के बाल-श्रमियों की संख्या महत्वपूर्ण है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बाल श्रम-जोखिम इन जिलों में केवल छिटपुट मामला नहीं, बल्कि संरचनात्मक चुनौती है। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि घरेलू श्रम की अदृश्यता के कारण वास्तविक जोखिम इससे अधिक हो सकता है, क्योंकि घर के भीतर होने वाले कामकाज की रिपोर्टिंग अक्सर कम होती है। इस दृष्टि से, जिला-स्तरीय संख्या को "न्यूनतम संकेत" मानना अधिक उपयुक्त है, यह हमें बताती है कि समस्या मौजूद है, पर घरेलू श्रम की परतें जोड़ने पर उसका विस्तार अधिक हो सकता है।

घरेलू कामकाज को जोखिम-श्रम के रूप में पहचानने के लिए समय-आधारित मानक एक व्यावहारिक आधार देते हैं। 21 घंटे प्रति सप्ताह की सीमा-रेखा इस बात का संकेतक बन सकती है कि कब घरेलू काम सामान्य मदद से आगे बढ़कर बच्चों की शिक्षा और कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने लगता है। यह सीमा-रेखा इसलिए उपयोगी है क्योंकि यह स्कूल-स्तर या समुदाय-स्तर पर सरल प्रश्नों के माध्यम से प्राथमिक पहचान की सुविधा देती है, बिना यह मान लिए कि हर घरेलू काम बाल श्रम है। इसी तरह, बिहार पर आधारित गुणात्मक संकेत यह पुष्ट करते हैं कि बच्चों के लिए स्कूल और घरेलू कामकाज साथ-साथ चलना एक वास्तविक सामाजिक तनाव है। यह तनाव केवल समय-बंधन का नहीं, बल्कि अपेक्षाओं, जिम्मेदारियों और सामाजिक भूमिकाओं का तनाव भी है, जहाँ बच्चे से यह उम्मीद की जाती है कि वह घर का काम भी "निपटा" दे और स्कूल में भी "उतना ही अच्छा" करे। दलित परिवारों में, जहाँ संसाधन और समर्थन सीमित हो सकते हैं, यह दोहरा दबाव अधिक तीखा हो जाता है।

इस संदर्भ में नागरिक समाज की भूमिका केंद्रीय है, क्योंकि घरेलू श्रम की अदृश्यता को तोड़ने के लिए समुदाय-स्तर पर भरोसे और संवाद की जरूरत होती है। नागरिक समाज स्थानीय स्तर पर यह काम कर सकता है कि घरेलू कामकाज का अत्यधिक समय-भार कब अधिकार-ह्रास में बदल रहा है, इसकी पहचान की जाए, परिवारों को विकल्पों और सहायता-मार्गों की जानकारी दी जाए, और स्कूल के साथ बच्चों की उपस्थिति व सीखने की निरंतरता पर संवाद कायम किया जाए। जब यह भूमिका शिकायत-समर्थन, समन्वय और अनुवर्तन तक जाती है, तब घरेलू श्रम का मुद्दा "निजी" से "सार्वजनिक" जिम्मेदारी की दिशा में बढ़ता है। नीति-स्तर पर भी समाधान का रास्ता किसी एक कार्यक्रम से नहीं, बल्कि संयुक्त मॉडल से होकर जाता है, जहाँ घरेलू श्रम-समय की पहचान, स्कूल-निरंतरता का सक्रिय समर्थन, परिवार-समर्थन की व्यावहारिक व्यवस्था और नागरिक समाज-राज्य समन्वय एक साथ काम करें। अंततः, मधुबनी और दरभंगा में दलित बच्चों के घरेलू श्रम को कम करने का लक्ष्य तभी टिकाऊ होगा जब घरेलू श्रम की अदृश्यता को संस्थागत निगरानी, समुदाय-आधारित जवाबदेही और अधिकार-आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से दृश्यमान और संबोधित किया जाए।

© Copyright @ Authors

Volume-9, Issue-2, July 2024 to December 2024
ISSN: 2348-473X
Impact Factor: 4.90

संदर्भ

1. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, “घरेलू कामकाज में बाल श्रम,” आधिकारिक वेब-सामग्री.
2. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, “बाल श्रम: सूचक-ढाँचा और घरेलू कार्य-सेवा की समय-सीमा,” आधिकारिक आँकड़ा.
3. बिहार सरकार, “बिहार राज्य बाल-अधिकार कार्ययोजना,” सरकारी दस्तावेज़, जिला-वार 5–14 आयु-वर्ग बाल-श्रम सारणी सहित.
4. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इनोचेंती, “बिहार में बाल श्रम और स्कूली शिक्षा में परिवर्तन के कारण,” रिपोर्ट, 2025.
5. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, “तस्करी-रोधी इकाई स्थापना/प्रचालन संबंधी योजना,” सरकारी दस्तावेज़.
6. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इनोचेंती, “भारत में बाल श्रम और स्कूली शिक्षा,” रिपोर्ट, 2024.
7. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इनोचेंती, “बाल श्रम घटाने में शिक्षा-रणनीतियाँ: भारत पर केंद्रित साहित्य समीक्षा,” चर्चा-पत्र, 2024.
8. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, “विद्यालय से बाहर बच्चों को मुख्यधारा में लाने के संदर्भ में योजना-कार्यान्वयन पर अध्ययन,” रिपोर्ट.

© Copyright @ Authors